

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1652
11 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन

1652. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

डॉ. सुभाष रामराव भाषरे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और तमिलनाडु में शुरू की गई केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त स्वास्थ्य लाभ योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अधीक्षण एवं निगरानी के लिए कोई समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त योजनाओं की दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए इनके तहत निधि के आवंटन में वृद्धि करने हेतु महाराष्ट्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): मंत्रालय की विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन जारी किया जाता है और इन योजनाओं के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का डाटा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रखा जाता है।

(ख): "जन स्वास्थ्य और अस्पताल" राज्य का विषय है, विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों की है। इसके अलावा, मंत्रालय कई निगरानी तंत्रों के माध्यम से इन योजनाओं के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी कर रहा है जिसमें संरचित मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण, संबंधित कार्यक्रम प्रभागों के अधिकारियों द्वारा दौरा, आवधिक समीक्षा बैठकें/संयुक्त

निगरानी मिशन, बाहरी सर्वेक्षण, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस), नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा, योजना आयोग द्वारा मध्यावधि मूल्यांकन आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ): किसी राज्य का वार्षिक संसाधन दायरा उसकी जनसंख्या और भारिता (वेटएज) घटक पर आधारित होता है जो राज्य के क्षेत्रफल, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन पर निर्भर करता है। इसके अलावा, सरकार ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मजबूत करने के लिए और अधिक धन आवंटित कर रही है।
